

## लॉकडाउन (वर्ष 2020) के दौरान रोज़गार का नुकसान

### प्रलिस के लयः

ऑल-इंडया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेसड एम्प्लॉयमेंट सर्वे

### मेन्स के लयः

श्रम बाज़ार पर रोज़गार का प्रभाव

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय' ने कोवडि महामारी के कारण वर्ष 2020 में लागू [लॉकडाउन](#) के दौरान नौकरी छूटने के आँकड़े प्रस्तुत कये हैं।

- डेटा 'ऑल-इंडया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेसड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (AQEES) पर आधारति है।

SECTORS	NUMBER OF EMPLOYEES (IN LAKH)			
	Prior to Lockdown (before March 25, 2020)		As on July 1, 2020	
	Male	Female	Male	Female
Manufacturing	98.7	26.7	87.9	23.3
Construction	5.8	1.8	5.1	1.5
Trade	16.1	4.5	14.8	4
Transport	11.3	1.9	11.1	1.9
Education	38.2	29.5	36.8	28.1
Health	15	10.6	14.8	10.1
Accommodation & Restaurants	7	1.9	6.2	1.7
IT/BPOs	13.6	6.3	12.8	6.1
Financial Services	11.5	5.9	11.3	5.7
// Total*	217.8	90.0	201.5	83.3

## प्रमुख बडि

### परचयः

- श्रम ब्यूरो द्वारा 'ऑल-इंडया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेसड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' को नौ चयनति क्षेत्रों के संगठति और असंगठति दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतषिठानों के संबंघ में तमिाही आधार पर अद्यतन करने के लयि आयोजति कयि जाता है।
  - 9 क्षेत्र वनिरिमाण, नरिमाण, वयापार, परविहन, शकिषा, स्वास्थय, आवास और रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ, वत्तीय सेवा गतविधियि हैं।
- घटकः
  - त्रैमासकि रोज़गार सर्वेक्षण (QES): यह 10 या उससे अधकि श्रमकिों को रोज़गार देने वाले प्रतषिठानों का सर्वेक्षण करता

है।

- संशोधित QES का आयोजन पहली तमिाही (अप्रैल-जून 2021) के दौरान किया गया था।
- पेरोल डेटा के साथ संख्या में अंतर का हवाला देते हुए वर्ष 2018 में QES के पुराने संस्करण को नलिंबति कर दिया गया था।
- **‘एरथिा फरेम इस्टैब्लिशमेंट सर्वे’ (AFES):** यह नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम शर्मकिों के साथ) को कवर करता है।

#### ■ प्रमुख नषिकर्ष:

- **वनिरिमाण क्षेत्र:** इसने प्री-लॉकडाउन (मार्च 2020) और पोस्ट-लॉकडाउन (जुलाई 2020) की अवधि के बीच 14.2 लाख नौकरयिों का नुकसान दर्ज किया।
  - वर्ष 2020 में लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 7.5% नौकरयिों का नुकसान हुआ।
- **वतितीय सेवा क्षेत्र:** सर्वेक्षण में इसी अवधि के दौरान आईटी/बीपीओ क्षेत्र में 0.4-1 लाख की नौकरी का नुकसान दर्ज किया गया।
- **अन्य क्षेत्र:** नरिमाण क्षेत्र में 1 लाख नौकरयिों का नुकसान दर्ज किया गया, जबकि वियापार और शकिषा क्षेत्रों में क्रमशः 1.8 लाख और 2.8 लाख नौकरयिों का नुकसान दर्ज किया गया।
- **महलिा कामगार:** नौ प्रमुख क्षेत्रों में महलिाओं ने 7.44% नौकरयिों गँवाई हैं।
  - वनिरिमाण क्षेत्र में महलिा रोजगार 26.7 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 23.3 लाख (जुलाई 2020 तक) हो गया।
  - नरिमाण क्षेत्र में महलिा शर्मकिों की संख्या 1.8 लाख से घटाकर 1.5 लाख हो गई।
  - वियापार क्षेत्र में महलिा रोजगार 4.5 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 4 लाख (1 जुलाई, 2020 तक) हो गया।
- **पुरुष शर्मकि:** प्री-लॉकडाउन और पोस्ट-लॉकडाउन अवधि के मध्य पुरुषों की 7.48% नौकरयिों का नुकसान दर्ज किया गया।
  - इसी अवधि के दौरान वनिरिमाण क्षेत्र में पुरुष कामगार 98.7 लाख से घटकर 87.9 लाख हो गए।
  - नरिमाण क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पुरुष शर्मकिों की संख्या 5.8 लाख से घटाकर 5.1 लाख हो गई।
  - वियापार क्षेत्र में पुरुष रोजगार 16.1 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 14.8 लाख (जुलाई 2020 तक) हो गया।

#### ■ नवीनतम नषिकर्ष:

- सतिंबर में जारी नए तमिाही रोजगार सर्वेक्षण में प्रमुख नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर अप्रैल-जून 2021 में 3.08 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 2.37 करोड़ था।
  - इसके लिये आधार वर्ष छठी आर्थिक जनगणना के आधार पर चुना गया था।
- महामारी के कारण 27% प्रतिष्ठानों में संगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है।
  - लॉकडाउन अवधि (मार्च 2020-जून 2020) के दौरान 81% शर्मकिों को पूरा वेतन मिला, 16% को कम मज़दूरी मलिी और केवल 3% शर्मकिों को कोई वेतन नहीं मलिा।

#### ■ महत्त्व:

- इन सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी सरकार को महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझने और साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने में मदद करेगी।
  - इसके अलावा मंत्रालय ने ‘प्रवासी कामगारों का अखलि भारतीय सर्वेक्षण’ और ‘घरेलू कामगारों पर अखलि भारतीय सर्वेक्षण’ नाम से दो और सर्वेक्षण शुरू किये हैं।

#### ■ संबंधित पहलें:

- [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना](#)
- [पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना \(DDU-GKY\)](#)
- [दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)
- [‘आत्मनरिभर भारत पैकेज 3.0’ के हसिसे के रूप में आत्मनरिभर भारत रोजगार योजना](#)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस